मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पाठ्य-पुस्तकों में आपत्तिजनक पाठ

169. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में विहित पाठ्य-पुस्तकों में कितने पाठ आपत्तिजनक पाए गए;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन पाठ्य-पुस्तकों की संख्या तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें इन आपत्तिजनक पाठों का पता लगाया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) स्कूली पाठ्य-पुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में है, द्वारा 1992 में उत्तर प्रदेश के स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की गई।

समिति के सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार समिति ने कक्षा और के लिए निर्धारित इतिहास की दो पाठ्य-पुस्तकों तथा गणित की दो पाठ्य-पुस्तकों को हटाने की सिफारिश की। यह सिफारिश इन पाठ्य-पुस्तकों के विभिन्न पाठों में आपत्तिजनक पाई गई सामग्रियों पर आधारित थी।

इन पाठ्य-पुस्तकों को हटाने की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार से की गई। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने नीचे सूचीबद्ध इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों को हटाने तथा गणित की पुस्तकों मे वैदिक गणित के इतिहास को निकालने का निर्णय लिया है। जिन पाठ्य-पुस्तकों में आपत्तिजनक पाठ पाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :

1. हाई स्कूल इतिहास–भाग-I
2. हाई स्कूल इतिहास–भाग-II
3. हाई स्कूल गणित–भाग-I
4. हाई स्कूल गणित–भाग-II

राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा नहीं की गई है।

Report on Education of Minorities

170. SHRI MOHAMMED AFZAL alias NEEM AFZAL : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received the report of the task force pertaining to education of Minorities on 23rd July, 1992 ; and

(b) if so, what action Government have taken on this report ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) The Task-Force of Minorities education, one of the 22-Task-Forces set up to revise the Programme of Action (POA), submitted its report on 23rd July, 1992.

(b) The report was suitably incorporated in the Programme of Action (POA), 1992 which was tabled in the Parliament on 19th August, 1992.

In pursuance of the programmes set out in the POA, 1992 two new central schemes, viz., scheme of financial assistance for Modernisation of Madras education and scheme of area intensive programme for educationally backward Minorities, have been approved. Under the scheme of Community Polytechnic, all the 41 Minority concentration districts identified by the POA have been covered.

The University Grants Commission has revamped the scheme of Coaching Classes for competitive examinations for students from Minority Communities.